www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 260 | जौनपुर सोमवार, 11 मई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

पंजाब में ड्रग्स वाली तबाही पर सीजेआई सूर्यकांत ने भी जताई चिंता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत ने पंजाब में ड्रग्स की बढ़ती समस्या पर गंभीर चिंता जताई है और राज्य में केंद्र की दखल की जरूरत बताई है। हालांकि ऐसे कदम उठाने से पहले सीजेआई ने केंद्र सरकार को भी ताकीद किया है कि वह यह न समझे कि वह दखलंदाजी कर रहा है बल्कि हम सबका साझा लक्ष्य नशे की समस्या पर लगाम लगाना होना चाहिए। शुक्रवार को इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की, शायद केंद्र सरकार के दखल की जरूरत पड़ सकती है लेकिन जब वे दखल दें, तो ऐसा न सोचें कि केंद्र दखलंदाजी कर रहा है। हमारा साझा लक्ष्य नशे की समस्या पर लगाम लगाना होना चाहिए। सीजेआई की यह चिंता और केंद्र को यह नसीहत इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीजाआई ने आगे कहा, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। एक माँ रो रही है। उसने नशे की वजह से अपना पांचवां बेटा खो दिया है। उसने नशे की लत के कारण अपने सभी बच्चे खो दिए। पुलिस को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। हम जानते हैं कि किसे गिरफ्तार किया जा रहा है और किसे छोड़ा जा रहा है। ड्रग्स के मामलों में बढ़ोतरी इतनी चिंताजनक है कि स्थिति पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी पहुंची

चंडीगढ़, (एजेंसी)। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर शनिवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की। सेक्टर–2 स्थित आवास पर सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम पहुंची। जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारी लगभग 20 गाड़ियों में मंत्री संजीव अरोड़ा के यहां मौके पर पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआईए और स्पेशल फोर्स के करीब तीन दर्जन जवानों को भी तैनात किया गया। सुबह 7रू25 बजे से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जो कई घंटों तक जारी रहा।जानकारी के मुताबिक, ईडी की यह कार्रवाई कथित मनी लॉन्ड्रिंग, एईएमए उल्लंघन, जमीन से जुड़े मामलों और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच के तहत की जा रही है। एजेंसी ने केवल चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि लुधियाना, जालंधर और गुरुग्राम समेत कई शहरों में भी छापेमारी की। जांच के दायरे में संजीव अरोड़ा के परिवार और उनकी कंपनी से जुड़े कुछ कार्यालय भी शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के समय संजीव अरोड़ा देश में मौजूद नहीं थे। वे आधिकारिक दौरे पर नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम गए हुए हैं।

सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

बंगाल, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार को एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई और सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोलकाता में आयोजित भव्य समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने सुवेंदु अधिकारी और उनके साथ पांच अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुवेंदु अधिकारी के साथ जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदिराम टुडू और निसिथ प्रमाणिक शामिल हैं। भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही राज्य में पहली बार किसी दक्षिणपंथी दल की सरकार बनी है। 8 मई को भाजपा विधायक दल ने सुवेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना था। इसके बाद उनका मुख्यमंत्री बनना तय हो गया था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करते हुए राज्य की सत्ता पर कब्जा जमाया। सुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर तीन दशक से अधिक लंबा रहा है। उन्होंने 1995 में कांथी नगरपालिका से पार्षद के रूप में राजनीति की शुरुआत की थी। इसके बाद वे तीन बार पार्षद रहे और कांथी नगरपालिका के चेयरमैन भी बने। उन्हें 20 साल से अधिक का विधायी अनुभव है। वे दो बार लोकसभा सांसद, तीन बार विधायक और पांच साल तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। राज्य सरकार में रहते हुए उन्होंने परिवहन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। इसके अलावा वे हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के चेयरमैन भी रहे। हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने औद्योगिक शहर हल्दिया के विकास में अहम

भूमिका निभाई। सहकारिता आंदोलन में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। वे एग्रीकल्चर रूरल बैंक, कांथी अर्बन कोऑपरेटिव और विद्यासागर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं। सुवेंदु अधिकारी का परिवार भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा है। कांथी के प्रसिद्ध अधिकारी परिवार के बिपिन अधिकारी और केनाराम अधिकारी बंगाल के कई स्वतंत्रता सेनानियों के करीबी सहयोगी थे। बिपिन अधिकारी को अंग्रेजों ने जेल भेजा था और ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकारी परिवार का घर दो बार जला दिया गया था। 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के करकुली गांव में जन्मे सुवेंदु अधिकारी ने रवींद्र भारती विश्वविद्यालय से एम.ए. की पढ़ाई की है। वे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री शिशिर अधिकारी के पुत्र हैं और फिलहाल अविवाहित हैं। सुवेंदु अधिकारी 2007 के नंदीग्राम आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे, जिसने 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। वे लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस में रहे और 2020 तक ममता बनर्जी सरकार में मंत्री भी थे। दिसंबर 2020 में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया था। उन्हें 'जायंट किलर' भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 2021 में नंदीग्राम और 2026 में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की।

दिल्ली सरकार ने सेंट्रल रिज क्षेत्र के 673.32 हेक्टेयर हिस्से को घोषित किया आरक्षित वन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सेंट्रल रिज क्षेत्र के 673.32 हेक्टेयर हिस्से को 'आरक्षित वन' घोषित कर दिया है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत जारी इस अधिसूचना के बाद राजधानी के इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा मिल गई है। इस क्षेत्र में सरदार पटेल मार्ग और राष्ट्रपति भवन के आसपास के हिस्से शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला दिल्ली की प्राकृतिक विरासत, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि रिज क्षेत्रों को कानूनी संरक्षण देने की प्रक्रिया कई दशकों से लंबित थी, जिसे अब उनकी सरकार ने पूरा किया है। हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण के विस्तार और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दिल्ली रिज अरावली पर्वतमाला का विस्तार है और इसे राजधानी के "ग्रीन लंग्स" यानी हरे फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र वायु गुणवत्ता सुधारने, भूजल स्तर बनाए रखने, जैव विविधता को संरक्षित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1994 में दिल्ली के पांचों रिज क्षेत्रों को पहली बार भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया था, लेकिन उन्हें अंतिम कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाई थी। पिछले वर्ष दक्षिणी रिज के 4080.82 हेक्टेयर क्षेत्र को 'आरक्षित वन' घोषित किया गया था और अब सेंट्रल रिज के 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को यह दर्जा दिया गया है।

पीएम मोदी का 10–11 को कर्नाटक, तेलंगाना व गुजरात दौरा, तेलंगाना को देंगे 9400 करोड़ की सौगात

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 मई को कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई धार्मिक, सामाजिक और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री 10 मई की सुबह बेंगलुरु पहुंचेंगे, जहां वे 'आर्ट ऑफ लिविंग' के 45वें स्थापना दिवस समारोह और गुरुदेव श्रीश्री रविशंकर के 70वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे बेंगलुरु स्थित 'आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर' में नवनिर्मित 'ध्यान मंदिर' का उद्घाटन करेंगे। यह ध्यान केंद्र आंतरिक शांति और

मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री संस्था की मानसिक कल्याण, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी कई नई सेवा पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे, जहां वे करीब 9,400 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें हैदराबाद–पणजी आर्थिक गलियारे के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग–167 के गुड्डेबेल्लूर से महबूबनगर तक चार लेन विस्तार परियोजना प्रमुख है, जिसकी लागत 3,175 करोड़ रुपये से अधिक है। इस परियोजना से यात्रा समय में लगभग डेढ़ घंटे की कमी आएगी और तेलंगाना– कर्नाटक के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री संगारेड्डी जिले में जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया की आधारशिला भी रखेंगे। लगभग 2,350 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग और मशीनरी उद्योगों के लिए बड़ा केंद्र बनेगी। इससे करीब 10,000 करोड़ रुपये के निवेश और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की उम्मीद है। वारंगल में प्रधानमंत्री देश के पहले पूर्ण रूप से संचालित पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन करेंगे। लगभग 1,700 करोड़ रुपये की लागत वाला यह मेगा टेक्सटाइल पार्क भारत सरकार के '5एफ विजन' को साकार करेगा और वैश्विक व्यापार के लिए आधुनिक लॉजिस्टिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

अभिषेक बनर्जी का चुनाव आयोग पर हमला, ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में करेंगे लोकतंत्र की रक्षा

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। इसके साथ आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ। भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री बनाया है। भाजपा ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के साथ लंबे समय से सत्ता पर राज कर रही है ममता बमर्जी की टीएमसी को उखाड़ फेंका है। सुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से हरा कर मुख्यमंत्री की सीट हासिल की। शपथ ग्रहण के बाद टीएमसी के नेता और डायमंड हार्बर सीट से लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके सरकारी एजेंसियों और भारत के चुनाव आयोग का

रवैया कितना पक्षपातपूर्ण बताया है। उन्होंने लिखा "हमने एक बेहद मुश्किल चुनाव लड़ा है, जिसमें कथित तौर पर लगभग 30 लाख असली वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, हमने देखा कि कई सरकारी एजेंसियों और भारत के चुनाव आयोग का रवैया कितना पक्षपातपूर्ण था। लोकतांत्रिक संस्थाएं, जिन्हें निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, वे भी सवालों के घेरे में दिखीं। इससे पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।" आग उन्होंने आरोप लगाया कि वोटों की गिनती से लेकर ईवीएम को लाने–ले जाने और उनके रखरखाव से जुड़े आरोपों तक जैसे कि कंट्रोल यूनिट का मेल न खाना, कई ऐसी परेशान करने वाली घटनाएं हुईं, जिनसे लाखों लोगों के मन में यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या लोगों के असली जनादेश का सम्मान किया गया है। मैंने पहले ही वोटों की गिनती वाले केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज जारी करने और वीवीपैट पर्चियों की पारदर्शी तरीके से गिनती कराने की मांग की है, ताकि सच लोगों के सामने आ सके और हर शक–शुबहे का जवाब खुले और ईमानदारी से दिया जा सके। आगे उन्होंने टीएमसी की हार से दुखी होकर लिखा, लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है, जब चुनावी संस्थाएं नागरिकों के मन में भरोसा और विश्वास जगाएं। दुर्भाग्य से, हमने जो कुछ देखा है।

तमिलनाडु में टीवीके समर्थक ड्राइवर–कंडक्टर बनाएंगे अलग यूनियन, पार्टी नेतृत्व से मांगा समर्थन

चेन्नई, (एजेंसी)। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके का प्रभाव अब सरकारी परिवहन कर्मचारियों के बीच भी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। चुनावी सफलता से उत्साहित तमिलनाडु राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) के कुछ कर्मचारियों ने अब टीवीके से जुड़ा एक नया ट्रेड यूनियन बनाने की पहल शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी) के कई बस चालक और परिचालक, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर टीवीके का समर्थन किया था, उन्होंने पार्टी की जीत का जश्न मिठाइयां बांटकर और विभिन्न शाखा कार्यालयों के बाहर जुटकर मनाया। अब टीवीके समर्थक कर्मचारी टीएनएसटीसी और राज्य एक्सप्रेस परिवहन निगम (एसईटीसी) के भीतर एक स्वतंत्र कर्मचारी यूनियन बनाने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि यह यूनियन उसी तरह काम करेगी जैसे डीएमके और एआईएडीएमके से जुड़ी मजबूत यूनियन वर्षों से परिवहन निगमों में प्रभाव रखती आई हैं। सूत्रों का कहना है कि टीवीके समर्थक परिवहन कर्मचारियों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क कर यूनियन को औपचारिक मान्यता और संगठनात्मक सहयोग देने की मांग की है। पार्टी नेतृत्व ने भी इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और यूनियन की संरचना तथा नेतृत्व को लेकर शुरुआती चर्चा शुरू हो चुकी है।

महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट फैलाना पड़ेगा भारी कानून मजबूत करने के लिए बनी समिति

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र सरकार सोशल मीडिया पर बिना सबूत बदनामी फैलाने के मामलों को लेकर गंभीर हो गई है। राज्य में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर बिना किसी प्रमाण के लोगों की छवि खराब करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे समाज के कई वर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण और लोगों की प्रतिष्ठा की बेहतर कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कानून में बदलाव या नई कानूनी व्यवस्था की संभावना की जांच के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। यह समिति सोशल

मीडिया के माध्यम से होने वाली बदनामी, फेक पोस्ट और बिना प्रमाण के लगाए जाने वाले आरोपों पर कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करेगी। साथ ही यह भी जांच करेगी कि मौजूदा कानूनों में संशोधन या नई धाराओं की आवश्यकता है या नहीं। राज्य सरकार ने इस समिति को यह जिम्मेदारी भी सौंपी है, कि वह राज्य स्तर पर नया कानून बनाने या मौजूदा कानून में संशोधन की संभावनाओं की कानूनी और तकनीकी जांच करे। इसके साथ ही सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कानून को और मजबूत बनाने संबंधी सिफारिशें सरकार को सौंपे।

बंगाल में पीएम मोदी ने कार्यकर्ता के छुए पैर, शुभेंदु को लगाया गले, मंच पर हुए दंडवत

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आजादी के बाद पहली बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को दंडवत प्रमाण किया। चुनाव विश्लेषण शुभेंदु अधिकारी के साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनिया, क्षुदीराम टुडु, निशिथ प्रमाणिक इन पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली हैं। शुभेंदु ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल में अब सोनार बांग्ला के नए दौर की आधिकारिक शुरुआत

हो रही है। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार का अभिनंदन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। 98 वर्ष की आयु में भी श्री माखनलाल सरकार स्वतंत्रतोत्तर भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती जमीनी स्तर के नेताओं में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी ने मंच पर रखी गई गुरुदेव टैगौर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए।भाजपा नेता दिलीप घोष शुभेंदु के मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। घोष की बात करें तो वो पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर सदर से चुनाव जीते हैं। उन्होंने सात बार के विधायक ज्ञान सिंह सोहनपाल को हराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य वरिष्ठ एनडीए नेता समारोह में मंच पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सहित भाजपा शासित प्रदेशों के सीएम ने इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती और पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बातचीत करते हुए नजर आए।

संपादकीय

दुर्भाग्यपूर्ण सूरत में तब्दील

वेदांता कंपनी के बिजली संयंत्र में बॉयलर फटने से कम–से–कम 14 मजदूर मारे गए और 30 से ज्यादा कर्मचारी घायल हो गए। अनुमान लगाया जा सकता है कि ये खबर मीडिया में महज एक दिन की सुर्खी बन कर रह जाएगी। भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति किस तरह मजदूरों के लिए ईज ऑफ डाइंग की दुर्भाग्यपूर्ण सूरत में तब्दील हो गई है, उसकी एक ताजा मिसाल छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हुआ हादसा है। सिंघीतराई में स्थित वेदांता कंपनी के बिजली संयंत्र में मंगलवार को बॉयलर फटने से कम–से–कम 14 मजदूरों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा कर्मचारी घायल हो गए। अनुमान लगाया जा सकता है कि ये खबर मीडिया में महज एक दिन की सुर्खी बन कर रह जाएगी। ना तो नीति–निर्माता, ना मीडिया कर्मी और ना ही सामाजिक कार्यकर्ता ये सवाल उठाने की जरूरत महसूस करेंगे कि आखिर ऐसी औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या हाल के वर्षों में क्यों बढ़ती चली गई है? सिर्फ 2026 पर नजर डालें, तो अब तक कारखानों में कम–से–कम ऐसे सात बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें मजदूरों की जान गई है। ये दुर्घटनाएं छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, और आंध्र प्रदेश तक में हुईं। बीते हफ्ते तेलंगाना में एक रासायनिक कारखाने में भीषण विस्फोट हुआ, हालांकि उसमें किसी जान नहीं गई। हलकी आग, छत गिरने या गैस लीक होने जैसी ऐसी घटनाओं की सूची तो लंबी है, जिनमें हताहत होने वाले मजदूरों की संख्या सीमित रहती है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2024 से 2026 में अब तक औद्योगिक हादसों में 296 मजदूरों की जान गई है। एक अध्ययन के मुताबिक देश में हर रोज औसतन तीन श्रमिकों की जान औद्योगिक हादसों में जाती है। इनमें से ज्यादातर मामलों को मामूली मुआवजा देकर निपटा दिया जाता है। मगर हादसों की जड़ में जाने और उसके लिए प्रबंधन को जवाबदेह बनाने की चर्चा शायद ही कभी सुनने को मिलती हो। कानून की किताब में ऐसे प्रावधान हों भी, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जमाने पर उन्हें गंभीरता से लेने का चलन नहीं रहा। स्पष्टतरू कारोबार में ये आसानी श्रमिकों की कीमत पर है। अतरू याद रखना चाहिए कि ऐसी कारोबारी आसानी से निवेशकों को मुनाफा बढ़ाने में भले आसानी होती हो, उससे फूलता– फलता उपभोक्ता बाजार तैयार नहीं हो सकता। ना ही ये कारोबारी संस्कृति आम खुशहाली का आधार बन सकती है।

भाजपा को परखने के औजार बदलने होंगे

राकेश

भारतीय जनता पार्टी की बंगाल जीत ने केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषकों का भी ध्यान आकर्षित किया है। सभी अपने–अपने मापदण्डों पर इस चुनाव परिणाम को परख रहे हैं परन्तु पुराने ढर्रों पर चलते हुए फिर से गलती पर गलती दोहराते लगते हैं। यहां के विपक्ष की मानें तो यह एसआईआर के प्रयोग से निकला विजयमार्ग है तो विदेशी विश्लेषक फिर से जिंगल बैल जिंदल बैल की तरज पर साम्प्रदायिकता का गीत गाने लगे हैं। इन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम बताते हैं कि भाजपा ने कहीं पहली बार पांव जमाए हैं, कहीं वह फिर से सत्ता में आई है तो कहीं उसने अपना जनाधार बढ़ाया है। अगर केरल जैसे राज्य में वामपंथी दलों को भाजपा के प्रभाव के डर से अयप्पा के दर्शन करने पड़ें, भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से बंजर कहे जाने वाले बंगाल में कमल की फसल लहलाने लगे, द्रविड़ राजनीति के केंद्र तमिलनाडू में उसकी आहट सुनने लगे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि विरोधी इस दल को गलत औजारों से परख रहे हैं। विरोधी भूलते हैं कि देश का मतदाता मदिहीन नहीं है, वह सुशासन व विकास को अपनी पसंद बनाता जा रहा है। अगर कोई दल संविधान के अनुरूप काम करते हुए जनता की पसंद बन रहा है तो विरोधियों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। भाजपा केंद्र और बहुत से राज्यों में वर्षों से शासन में है। अंधविरोध के चरम पर जा कर भी शासन व संवैधानिक व्यवस्था के किसी मान्य मापदण्ड पर विपक्ष अभी तक ऐसा कोई मुद्दा तराश नहीं पाया है जो जनता को भी मान्य हो। यहां तक कि प्रधानमंत्री कई बार चुटकी ले चुके हैं कि सार्वजनिक जीवन में विपक्ष उनकी कोई तथ्यात्मक आलोचना करने में असफल रहा है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता तक पहुंचते ही वैश्विक वैचारिक गलियारों में भी बेचैनी पैदा हो गई है। विदेशी मीडिया के बड़े हिस्से ने भारत में लोकतंत्र, अल्पसंख्यक अधिकार और चुनावी निष्पक्षता पर अचानक सवाल उठाने शुरू कर दिए। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन और अल जजीरा जैसे मंचों पर फिर से यह विमर्श तेजी से गढ़ा जाने लगा कि भारत हिन्दू राष्ट्रवाद की ऐसी दिशा में बढ़ रहा है, जहां लोकतंत्र व बहुलता खतरे में है। विदेशी मीडिया में ज्यादा चर्चा बंगाल की है। सवाल यही है कि क्या चिंता वास्तव में लोकतंत्र की है या उस सियासी बदलाव की, जिसने दशकों पुराने वामपंथ और छद्मधर्मनिरपेक्षता के वैचारिक गढ़ को ध्वस्त कर दिया? जब भाजपा हारती है, तो विदेशी मीडिया भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता की तारीफ करता है, पर जैसे ही वह निर्णायक जनादेश लेकर आती है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया संदेह और संस्थागत संकट की भाषा में बदल जाती है। श्रेष्ठभावना से ग्रसित पश्चिमी जगत कहीं यह तो नहीं मानता कि भारतीय मतदाताओं में राजनीतिक समझ का अभाव है ? राष्ट्रवाद को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर अनेक विचारक स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत का राष्ट्रवाद संकीर्ण पश्चिमी राष्ट्रवाद से सर्वदा विपरीत है। पश्चिमी मीडिया भारत को अक्सर यूरोपीय राजनीतिक अनुभवों के चश्मे से देखने की कोशिश करता है। वहां राष्ट्रवाद का अर्थ सत्ता विस्तार व नस्लीय वर्चस्व रहा है। जबकि भारत में राष्ट्रवाद सांस्कृतिक, सभ्यतागत पहचान और ऐतिहासिक आत्मबोध से जुड़ा है। इसे विदेशी मीडिया समझ नहीं पाता। इसीलिए वो हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण को सीधे अल्पसंख्यक–बहुसंख्यकवाद से जोड़ देता है। यही कारण है कि बंगाल में भाजपा की जीत को पश्चिम के विश्लेषकों ने लोकतांत्रिक परिवर्तन के बजाय हिंदू राष्ट्रवादी कब्जे की तरह प्रस्तुत किया गया। एसआईआर पर अर्धसत्य दिखाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परिणामों के बाद वोट चोरी का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भाजपा का आयोग बताया। विदेशी मीडिया ने इन आरोपों को लगभग बिना तथ्य जांचे ही अपने विमर्श का आधार बना लिया। विशेष रूप से एसआईआर को मुस्लिम मतदाताओं को हटाने की साजिश के रूप में पेश किया गया, जबकि हटाए गए 91 लाख नामों में 63 प्रतिशत हिंदू मतदाता थे। बड़ी संख्या में नाम मृत, डुप्लिकेट, स्थायी रूप से स्थानांतरित या फर्जी पाए गए थे। इसके बावजूद विदेशी मीडिया के बड़े हिस्से ने केवल मुस्लिम वोट हटाए गए वाली जिद को प्रमुखता दी। देसी–विदेशी विश्लेषक यह भूल गए कि जिन 20 सीटों पर जाँच के बाद सबसे ज्यादा वोट काटे गए थे, उनमें से ज्यादातर पर टीएमसी ने ही कब्जा जमाया है। इन सीटों में समशेरगंज, लालगोला, भगवानगोला, रघुनाथगंज, मटियाबुर्ज, सूती, मोथाबाड़ी, गोलपोखर, मालतीपुर, चोपड़ा, सुजापुर, राजारहाट न्यू टाउन और बशीरहाट उत्तर शामिल हैं। इन सभी 13 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी को जीत मिली है। अन्य सीटों की बात करें तो फरक्का सीट पर सबसे ज्यादा 38,222 वोट काटे गए थे, लेकिन वहाँ से कॉन्ग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं भाजपा को जंगीपुर, रतुआ, करनदिघी, केतुग्राम, मानिकचक और मोंतेश्वर जैसी 6 सीटों पर जीत मिली। यह अकेला आँकड़ा ही उस प्रोपेगेंडा की हवा निकाल देता है जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि वोटर लिस्ट में सुधार से सिर्फ टीएमसी को नुकसान हुआ और भाजपा को फायदा पहुँचा। अगर बड़े पैमाने पर देखें, तो जिन 187 सीटों पर 5,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए थे, वहां भाजपा ने 119 और टीएमसी ने 65 सीटों पर जीत दर्ज की। इन 187 सीटों में से 47 सीटें ऐसी थीं, जहाँ कटे हुए वोटों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी। भाजपा ने जो 119 सीटें जीतीं, उनमें से 28 सीटों पर जीत का अंतर कटे हुए वोटों से कम था। इन आँकड़ों से साफ है कि कई सीटों पर कांटे की टक्कर थी और वहाँ कटे हुए वोटों की संख्या जीत के मार्जिन से

ज्यादा रही। लेकिन हार का पूरा ठीकरा सिर्फ वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया पर फोड़ देना और इसे ही हार की एकमात्र वजह बताना पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। सच्चाई यह है कि देसी–विदेशी विश्लेषकों को नरेंद्र मोदी और भाजपा का बढ़ता राजनीतिक विस्तार विदेशी वैचारिक प्रतिष्ठानों की सबसे बड़ी बेचैनी बन चुका है। खास कर उन क्षेत्रों में यह जलन ज्यादा है जो 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस को मिली थोड़ी राजनीतिक राहत को लेकर उत्साहित चला आरहा था। आज भाजपा अधिकांश राज्यों में प्रत्यक्ष या गठबंधन के जरिए सत्ता में है। ऐसे में भारत को हिन्दू राष्ट्रवादी लोकतंत्र और एकदलीय प्रभुत्व के खांचे में फिट करने की कोशिशें और तेज होती दिख रही हैं। परंतु बंगाल का फैसला यह भी साबित करता है कि भारत का मतदाता अपनी प्राथमिकताएं जमीन, अनुभव और आकांक्षाओं के आधार पर तय कर रहा है, न कि न्यूयॉर्क, लंदन या दोहा में बैठे नैरेटिव निर्माताओं की वैचारिक दृष्टि के अनुसार। विदेशी विश्लेषणों में बंगाल के चुनावी परिणाम को हिन्दुत्व के उभार के रंग में रंग दिया। लेकिन वहां की जनता की नाराजगी, आर्थिक बदहाली, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीडन, सत्ताधारियों की हिंसा, उद्योगों का पलायन जैसे कारणों की अनदेखी कर गया। आज बंगाल पर कर्ज 7.7 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुका है। हजारों कंपनियां राज्य छोड़ चुकी हैं। युवाओं का बड़ा वर्ग रोजगार के लिए पलायन कर रहा है। महानगरों में घरों में काम करने वाली अधिकतर महिलाएं बंगाली ही निकलती हैं।

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन है वैचारिक बदलाव का संकेत

ललित

पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों को केवल एक राजनीतिक दल की जीत या हार के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह परिणाम उस वैचारिक संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरे हैं, जो लंबे समय से बंगाल की राजनीति के भीतर सुलग रहा था। वर्षों तक बंगाल को एक ऐसे राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां कथित रूप से जाति, धर्म और पहचान की राजनीति नहीं चलती, बल्कि विचारधारा, वर्ग–संघर्ष और बंगालियत की राजनीति प्रभावी रहती है। किंतु 2026 के चुनाव परिणामों ने इस स्थापित धारणा को गहराई से चुनौती दी है। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान में आए परिवर्तन का भी संकेत है। मतदाता अब केवल भावनात्मक नारों या वैचारिक रोमांटिसिज्म के आधार पर मतदान नहीं कर रहा, बल्कि वह अपनी सांस्कृतिक पहचान, सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और भविष्य को भी ध्यान में रख रहा है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व सफलता को अनेक विश्लेषक एक प्रकार के "सांस्कृतिक पुनर्जागरण" के रूप में देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में "बंगाली अस्मिता" और "हिंदू पहचान" के बीच एक वैचारिक द्वंद्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। तृणमूल कांग्रेस ने स्वयं को बंगाल की संस्कृति और क्षेत्रीय गौरव का संरक्षक बताया, जबकि भाजपा ने राष्ट्रीयता, हिंदुत्व और सांस्कृतिक चेतना को अपने राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाया। वास्तव में बंगाल की ऐतिहासिक चेतना कभी संकुचित नहीं रही। यह वही भूमि है जहाँ से स्वामी विवेकानंद, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, रवींद्रनाथ ठाकुर और नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे महापुरुषों ने भारतीय राष्ट्रवाद को नई दिशा दी। "वंदे मातरम्" का उद्घोष भी इसी भूमि से निकला। इसलिए जब बंगाल में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक अस्मिता की चर्चा होती है, तो वह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि भावनात्मक और ऐतिहासिक संदर्भ भी ग्रहण कर लेता है। भाजपा ने इसी ऐतिहासिक चेतना को पुनः जागृत करने का प्रयास किया। दुर्गापूजा, रामनवमी, हनुमान जयंती और हिंदू धार्मिक प्रतीकों को लेकर जिस प्रकार की राजनीतिक बहसें पिछले वर्षों में सामने आईं, उन्होंने हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग को यह महसूस कराया कि उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां राजनीतिक विवाद का विषय बन रही हैं। परिणामस्वरूप एक बड़ा वर्ग अपनी पहचान के प्रश्न पर अधिक मुखर हुआ। पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय से अल्पसंख्यक वोट बैंक के इर्द–गिर्द घूमती रही है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा कि ममता बनर्जी सरकार ने संतुलित शासन के बजाय तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। चाहे इमाम भत्ता का मुद्दा हो, धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रशासनिक निर्णय हों या सीमावर्ती जिलों में बदलता जनसांख्यिकीय संतुलन–इन सभी विषयों ने धीरे–धीरे हिंदू समाज के भीतर असंतोष को जन्म दिया। यह असंतोष केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी था। अनेक लोगों को यह लगने लगा कि राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता का अभाव है। भाजपा ने इसी भावना को राजनीतिक रूप दिया। उसने यह संदेश देने का प्रयास किया कि उसकी राजनीति केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि "सांस्कृतिक सुरक्षा" स्थापित करने की राजनीति है। यही कारण है कि चुनाव प्रचार के दौरान "जय श्रीराम" जैसे नारे केवल धार्मिक उद्घोष नहीं रहे, बल्कि वे एक प्रकार के राजनीतिक प्रतिरोध और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक बन गए। इस चुनाव में हिंदी भाषी मतदाताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। पिछले कुछ वर्षों में बंगाल के औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में हिंदी भाषी समाज का प्रभाव बढ़ा है। यह वर्ग लंबे समय से स्वयं को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करता रहा था। भाजपा ने इस वर्ग को संगठित करने में सफलता प्राप्त की। हालांकि इस चुनाव को केवल "हिंदी बनाम बंगाली" के दृष्टिकोण से देखना भी उचित नहीं होगा। वस्तुतः भाजपा ने हिंदी भाषी और स्थानीय हिंदू समाज के बीच एक वैचारिक सेतु बनाने का प्रयास किया। उसने यह संदेश दिया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर है। यही कारण है कि बंगाल के अनेक क्षेत्रों में भाजपा को व्यापक समर्थन मिला। पश्चिम बंगाल कभी वामपंथ का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। वर्ग–संघर्ष, श्रमिक राजनीति और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा यहाँ की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा रही। लेकिन समय के साथ यह विचारधारा जमीन से कटती चली गई। वामपंथी दल जनता की नई आकांक्षाओं, युवाओं की उम्मीदों और बदलते सामाजिक यथार्थ को समझने में असफल रहे। आज का युवा केवल वैचारिक भाषण नहीं चाहता– वह रोजगार, सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्मान और विकास चाहता है। यही कारण है कि वामपंथ धीरे–धीरे राजनीतिक हाशिये पर पहुँच गया। भाजपा ने इस खाली स्थान को भरते हुए स्वयं को एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सफलता को अनेक लोग डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों से भी जोड़कर देख रहे हैं। डॉ. मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विभाजनकारी राजनीति का विरोध किया और राष्ट्रीय एकात्मता को सर्वोपरि माना। बंगाल की राजनीति में भाजपा का उभार कहीं न कहीं उसी विचारधारा की पुनर्स्थापना के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि बंगाल अब केवल क्षेत्रीय राजनीति का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि वह पुनः राष्ट्रीय चेतना का नेतृत्व करेगा।

सोमनाथ- भारत की अजेय आत्मा का प्रतीक

नरेंद्र मोदी

जय सोमनाथ ! वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन, सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। छह महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा हैरू प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम्। अर्थात दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! जब लोग यहां दर्शन–पूजन के लिए आते हैं, तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकी। कई साम्राज्य आए और गए, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार–चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा। यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया था। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध अपनी सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की। महिपाल चूड़ासमा और राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा–पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई है। उनके साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। 1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वह थी– सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवंबर 1947 को, दिवाली के समय, उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर, समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, श्यइस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा। यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी।य्य उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया। दुर्भाग्यवश, सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। इससे पहले कि जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बावजूद, प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस किया जाता रहा है। उनके विजन को के.एम. मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जामसाहेब का समर्थन मिला। 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद, डॉ. प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एक निर्णायक एवं जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभरा

अर्जुन

यूक्रेन में जारी युद्ध के खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिखने और मध्य–पूर्व के न युद्ध, न शांति के दलदल में फंसे होने के बावजूद, हाल के समय के दूसरे संघर्षों के मुकाबले ऑपरेशन सिंदूर को एक मानक अभियान के तौर पर देखना महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खास बातें थींकृ सैन्य ताकत का तीव्र और नियंत्रित तरीके से निर्णायक इस्तेमाल, ताकि प्रबंधन करने योग्य संघर्ष–विस्तार में रहते हुए ऐसे रणनीतिक नतीजे हासिल किए जा सकें, जिनकी बाहर निकलने की रणनीति स्पष्ट हो और जो मोदी सरकार के राजनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप हों। इस संघर्ष की शुरुआत का उद्देश्य था – पाकिस्तान के भारत–विरोधी आतंकवादी नेटवर्क के गढ़ पर सीधा हमला करना और अगर पाकिस्तान की सेना भारत के शुरुआती आतंकवाद–रोधी हमले का सैन्य जवाब देती है, तो उसे भारी नुकसान पहुंचाना। ये ऐसे बड़े लक्ष्य नहीं थे, जिनके लिए बहुत बड़े पैमाने पर और हर तरफ सैन्य ताकत के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती। यह एक जिम्मेदार ताकत द्वारा, राज्य–प्रायोजित आतंकवाद के बार–बार दोहराए जाने वाले कृत्यों को सजा देने के लिए चलाया गया एक सटीक, सक्रिय और संयमित प्रतिरोधी अभियान था। हालांकि भारत ने 2019 में बालाकोट में आतंकवाद–रोधी अभियानों में आक्रामक हवाई शक्ति के इस्तेमाल का प्रयोग किया था, लेकिन इस बार जैश–ए–मोहम्मद और लश्कर–ए–तैयबा के मुख्यालयों परकृजो क्रमशरू बहावलपुर और मुरीदके में स्थित हैंकृ हमला करने की उसकी तत्परता ने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जोखिम उठाने की एक नई प्रवृत्ति और संघर्ष को बढ़ाने की इच्छाशक्ति को उजागर किया। फिर भी, राजनीतिक स्तर पर सोच में पूरी स्पष्टता थी कि एक व्यापक संघर्ष भारत के हित में नहीं है, भले ही पाकिस्तान की सैन्य परिसंपत्तियों को और अधिक नुकसान पहुँचाने का सैन्य प्रलोभन मौजूद था। समझदारी और संयम, जिम्मेदार राज–काज और सैन्य अभियानों के दो ऐसे साथ–साथ चलने वाले पहलू हैं, जिन्हें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अच्छी तरह प्रदर्शित कियाय खासकर इस मामले में कि उसने अपने हमलों के दौरान कोई भी अतिरिक्त नुकसान नहीं होने दिया और सैन्य श्रेष्ठता होने के बावजूद पाकिस्तान के युद्धविराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब पीछे मुड़कर देखने पर, एक लंबे और बड़े संघर्ष से मिलने वाले फायदे, उसके संभावित आर्थिक और मानवीय नुकसानों के मुकाबले बहुत ही मामूली लगते हैं। चार दिनों के भीतर ही संघर्ष को समाप्त कर देने से जो सैकड़ों करोड़ रुपये की बचत हुई, उसने मध्य–पूर्व में चल रहे मौजूदा संघर्ष के दौरान भारत की आर्थिक सहनीयता में योगदान दिया है। दूसरी ओर, मध्य–पूर्व के संघर्ष में अमेरिका के 27 अरब डॉलर से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं और इस संघर्ष का कोई अंत भी नजर नहीं आ रहा है। भारत के मौजूदा उच्च रक्षा संगठन ने संघर्ष के दौरान अच्छी तरह काम किया। ऑपरेशन के नीति–निर्माण और तैयारी के चरण में केंद्रीकृत और निर्देशात्मक नियंत्रण का एक स्पष्ट मॉडल देखने को मिलाय इसके पहले स्तर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री थे, जबकि दूसरे स्तर पर सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख इसे समर्थन दे रहे थे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सेना प्रमुखों और खुफिया एजेंसियों को स्पष्ट और ठोस रणनीतिक परिणाम बताए गए थे, जिसके बाद उन्हें एक व्यावहारिक कार्ययोजनाय तैयार करने की जिम्मेदारी दी गयी। भले ही हजारों सालों में युद्ध के स्वरूप में कई बदलाव आए हों, लेकिन कौटिल्य, सुन त्जू, क्लॉजविट्ज और लिडेल हार्ट जैसे प्राचीन और आधुनिक रणनीतिकारों द्वारा बताए गए युद्ध के अधिकांश मूल सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। कुल मिलाकर, ऑपरेशन सिंदूर की भारत की सफलता ने तनाव बढ़ाने और प्रतिरोध करने की सीमाओं का विस्तार किया, भारत ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि इसने समय की कसौटी पर खरे उतरे युद्ध के कुछ सिद्धांतों और संकट के समय फैसले लेने के तरीकों का पालन किया। इनमें से, लक्ष्य का चयन और उसे बनाए रखना, शक्ति का केंद्रीकरण, आक्रामक कार्रवाई, अचानक हमला, कमान की एकता, सुरक्षा, सरलता, मनोबल और अनुकूलनशीलता ऐसे सिद्धांत हैं, जिन पर और अधिक विचार–विमर्श की आवश्यकता है। परिचालन स्तर पर, भारत की उभरती हुई बहु–क्षेत्रीय सैन्य रणनीति के तलवार के रूप में आईएएफ का इस्तेमाल करने का फैसला एक साहसी कदम था, जो आज के दौर के संघर्षों के बदलते स्वरूप को दिखाता है और जिस पर बारीकी से नजर रखने और विश्लेषण करने की जरूरत है। पाकिस्तान की चीन से मिली वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने और उन्हें जाम करने के बाद, भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में घुसकर हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान और पीओजेके में मौजूद 9 अहम आतंकवादी ठिकाने तबाह हो गए, और लश्कर–ए–तैयबा, जैश–ए–मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख केंद्र नष्ट हो गए। 10 मई को, कुछ ही घंटों के भीतर, भारत ने अपने हमले का दायरा और बढ़ाया तथा 11 प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, जिनमें नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सुक्कुर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पसरूर एयरबेस, चुनियां एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, स्कार्दू एयरबेस, भोलारी एयरबेस और जैकोबाबाद एयरबेस शामिल थे। इस कार्रवाई से पाकिस्तान की हवाई और युद्ध संबंधी क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुँचा। आईएएफ की हवाई हमलों की तीव्रता से यह जाहिर हो गया है कि इन हवाई अड्डों, विमानों और वहाँ तैनात हथियार प्रणालियों को पहुँचाया गया नुकसान, 1971 के युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर आईएएफ द्वारा पीएएफ के हवाई अड्डों को पहुँचाए गए कुल नुकसान से कहीं ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की एकीकृत हवाई रक्षा प्रणाली की परिपक्वता को भी साबित कर दिया, जो दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन–केंद्रित रणनीति का मुकाबला करने में सक्षम है। हालाँकि, आईएएफ को भविष्य में, अधिक शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ किसी भी सीमित संघर्ष की स्थिति में अपने प्लेटफॉर्म, हथियारों और प्रणालियों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए, तेज गति से लगातार सीखते रहने की आवश्यकता होगी। भविष्य के युद्ध–क्षेत्रों में, लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों का सामना करने के लिए, ज्यादा एकीकरण और तालमेल की जरूरत होगी। वर्तमान में चल रहे सुधारों और संरचनात्मक पहलों पर शायद फिर से विचार करना पड़े, ताकि एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जा सके जो भारत–विशिष्ट हो और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीखे गए अनुभवों पर आधारित हो। हालांकि, दुनिया भर में चल रहे संघर्षों से कई रणनीतिक और परिचालन संबंधी सबक मिलते हैं।

सिंगरामऊ के गौरी शंकर मंदिर में धूमधाम से मनाया गया `सोमनाथ स्वाभिमान पर्व'

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. के आह्वान पर ठाकुर बाड़ी महिला विकास कल्याण समिति के मुख्यालय परिसर स्थित गौरी शंकर मंदिर में सोमवार को 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' श्रद्धा, उल्लास और धार्मिक वातावरण के बीच धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था प्रमुख डॉ. अंजू सिंह एवं सिंगरामऊ की ग्राम प्रधान श्रीमती मीना सिंह ने मंदिर में स्थापित शिवलिंग के विधिवत पूजन–अर्चन के साथ किया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चार, घ्कार जाप और भव्य महाआरती से भक्तिमय हो उठा। पूजन कार्यक्रम मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विनोद मिश्रा एवं महेंद्र शास्त्री द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर सामूहिक भजन–कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आए। साथ ही 'सोमनाथ संकल्प संवाद' कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को भारतीय गौरव, सांस्कृतिक अस्मिता और सनातन परंपराओं के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर मंदिर परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर सेवा और स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी अजय कुमार, बीडीसी सदस्य केशव प्रसाद, प्रधान प्रतिनिधि विनय सिंह, ग्राम पंचायत सदस्य हेमलता यादव, मुमताज अहमद, पीयूष बरनवाल सहित ठाकुरबाड़ी महिला विकास कल्याण समिति के अधिकारी–कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम में देरी पर महिलाओं का आक्रोश धरना प्रदर्शन कर महिलाओं ने उठाई 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी में महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी को लेकर सोमवार को जौनपुर में 'महिला जन आक्रोश' कार्यक्रम के तहत महिलाओं ने ध रना–प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार जल्द देने की मांग उठाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला मंत्री अंशु कुशवाहा ने कहा कि संसद और विध ानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी उनका अधिकार है, कोई खैरात नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने में हो रही देरी करोड़ों महिलाओं के सपनों और उम्मीदों में देरी है। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रागिनी सिंह ने भी धरना स्थल पर महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। रागिनी सिंह ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग महिलाओं के सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन संसद में महिला आरक्षण के मुद्दे पर विरोध और भ्रम फैलाने का काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की।

ज्येष्ठ माह में जी.एस. सोशल संस्था द्वारा भजन कीर्तन और विशाल भंडारे का आयोजन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ज्येष्ठ माह में संस्था जी.एस. सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी, लखनऊ के द्वारा और आपके सहयोग से मनपूर्णा मंदिर, निकट कोठारी बंधु पार्क, राजाजीपुरम,लखनऊ में भजन–कीर्तन तथा प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में भक्तों ने भजन कीर्तन गाकर आनंद की अनुभूति की और प्रसाद वितरण में साथ दिया और प्रसाद ग्रहण किया।कार्यक्रम की शुरुआत पार्षद श्री अनूप कमल सक्सेना और श्री शिव पाल सावरिया (पूर्व पार्षद)द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीपक प्रज्वलित करने के साथ हुआ, सभी सम्मानित लोगों का सम्मान संस्था जी.एस ग्रुप के श्री आलोक मिश्रा (उपाध्यक्ष–जी.एस. ग्रुप)द्वारा हुआ। श्री आलोक मिश्रा (उपाध्यक्ष–जी. एस. ग्रुप)द्वारा श्री अनूप कमल सक्सेना (पार्षद) और श्री शिवपाल सांवरिया (पूर्व पार्षद) को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया और व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री विकास सक्सेना और श्री रमेश शुक्ला(व्यापार मंडल–संरक्षक) का स्वागत श्री आलोक मिश्रा द्वारा अंग वस्त्र पहनाकर किया गया और श्रीमती शुभा श्रीवास्तव(उपाध्यक्ष) ने श्रीमती बीना गुप्ता,(पूर्व पार्षद)का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया और मनपूर्णा मंदिर प्रांगण में उपस्थिति संस्था जी.एस सोशल ग्रुप की ओर से सर्वश्री अनूपकमल सक्सेना (पार्षद),शिवपाल सावरिया (पूर्व पार्षद), श्रीमती बीना गुप्ता,(पूर्व पार्षद),राजीव अस्थाना, संतोष श्रीवास्तव भैया, रवि प्रकाश भैया, विनय तिवारी,मयंक गुप्ता,आनंद गुप्ता धर्मेंद्र भैया,विकास सक्सेना,अमित भईया,दीपक निगम, आशीष सिंह,रामजी,दिलीप पांडे, अमित,अवधेश भैया, पुरुषोत्तम भैया, नितिन भैया,मोहन भैया, शुभ भटनागर, मुक्तिनाथ झा , कौशल भैया,अभिषेक, हर्षित, तरुण श्रीवास्तव,आशीष तिवारी,मुकेश शुक्ला, रमाशंकर सोनकर,हरिओम भईया ,निखिल जायसवाल, सर्वश्रीमती शुभा श्रीवास्तव, मधु पराशर,मधु चौहान,मधु गुप्ता,योगिता मिश्रा, इशिता, परी,आदि लोगों ने ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल में द्वितीय शनिवार को बड़े हर्षोल्लास और भजनों का भरपूर आनंद के साथ मनाया और मंदिर में उपस्थित सभी महिला, पुरुषों और बच्चों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में भरपूर सहयोग दिया। अरुण कुमार शुक्ला ने सभी उपस्थित माताओं,भाइयों, बहनों और बच्चों का ह्रदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त किया।

प्रभारी निरीक्षक कैंट रेलवे स्टेशन अनिल प्रकाश सिंह ने किया स्टेशन परिसर का निरीक्षण

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।सोमवार को पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग लखनऊ के द्वारा दिए गए निर्देश की अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी कैंट रेलवे स्टेशन अनिल प्रकाश सिंह तथा उनकी टीम ने अयोध्या कैंट रेलवे

स्टेशन पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इधर से गुजरने वाले ट्रेनों खासकर तुलसी एक्सप्रेस,वंदे भारत सहित ट्रेनों के अंदर जाकर बारीकी से निरीक्षण किया और इस मौके पर ट्रेन के अंदर बैठे रेल यात्रियों से अपील किया कि आप सभी किसी भी अनजाने संदिग्ध व्यक्ति से दिए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन न करें।न ही उनके द्वारा दिए गए सामानों को ले।इस मौके पर उन्होंने अयोध्या कैंट स्टेशन पर सभी प्लेटफार्म,टिकट घर, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हाल, मेन गेट प्रतीक्षालय को सफलता से निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान रेलवे परिसर के अंदर बिना कारण बैठे हुए थे उनको बाहर किया। इस मौके पर उनके अलावा कांस्टेबल सतीश सिंह मनोज कुमार सहित क्यूआरटी की टीम मौजूद रही।

जौनपुर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर निकली भव्य कलश यात्रा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में शासन के निर्देश पर सोमवार को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन., मुख्य विकास अधिकारी ध रुव खाड़िया, अपर जिलाधिकारी अजय अंबष्ट एवं परमानन्द झा सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर डाक बंगला चौराहा होते हुए पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर पहुंची, जहां विधिवत पूजन–अर्चन किया गया तथा श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और भक्ति भाव देखने को मिला। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर धार्मिक वातावरण को और अधिक आकर्षक बना दिया। "हर–हर महादेव" के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। यात्रा मार्ग पर जगह–जगह पुष्पवर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी–कर्मचारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, छात्र–छात्राएं, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। कलश यात्रा के माध्यम से भारतीय संस्कृ ति, सनातन परंपरा और धार्मिक एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। इसके उपरांत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री तथा वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ ध ाम परिसर के त्र्यंबकेश्वर बहुउद्देशीय हॉल से मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के प्रेरणादायी उद्बोधन का सजीव प्रसारण देखा और सुना गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, डॉ. अजय सिंह, जिला महामंत्री पीयूष गुप्ता, पूर्व विधायक दिनेश चौधरी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, डॉ. अजय सिंह, पूर्व विध ायक दिनेश चौधरी समेत अन्य अतिथियों को अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

त्रिलोचन महादेव मंदिर परिसर में अनियंत्रित कार का कहर, पांच लोग गंभीर घायल, दो जिला अस्पताल रेफर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। आई टी यूपी के जौनपुर स्थित जलालपुर थाना क्षेत्र स्थित त्रिलोचन महादेव मंदिर परिसर में सोमवार सुबह उस समय अफरा–तफरी मच गई, जब एक नई स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं और राहगीरों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुछ अन्य लोगों को हल्की चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंदिर परिसर में काफी भीड़ मौजूद थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और वहां मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख–पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेहटी पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल अरविंद राजभर (32) निवासी कोड़री तथा प्रमोद कुमार (32) निवासी गढ़ कोड़री की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अन्य घायलों में विशाल मिश्रा (26) निवासी बराई, आयुष (21) निवासी बराई तथा अंजलि पटेल (14) निवासी करिखियाव, फूलपुर वाराणसी शामिल हैं। सीएचसी रेहटी के फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह ने बताया कि कुल सात लोगों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था। घटना के बाद मंदिर परिसर में कुछ समय के लिए अफरा–तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।मौके से गाड़ी को क्रेन द्वारा थाने पर लाकर जप्त किया गया है।हादसे में कोई मौत नहीं है।घायलों का इलाज चल रहा है।

संक्षिप्त खबरें

स्मार्ट प्री–पेड मीटर व्यवस्था समाप्त करने के फैसले पर कपिल देव अग्रवाल ने जताया आभार

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने शुक्रवार को कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से शिष्टाचार भेंट कर स्मार्ट प्री–पेड मीटर व्यवस्था समाप्त कर बाद भुगतान प्रणाली लागू किए जाने के निर्णय पर आभार व्यक्त किया।इस अवसर पर कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार जनहितकारी निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय उपभोक्ताओं को राहत देने वाला महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आम लोगों को सुविधा और पारदर्शिता दोनों का लाभ मिलेगा।ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून 2026 तक प्रदेशभर में विशेष शिकायत निस्तारण शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां उपभोक्ताओं की बिल संशोधन तथा तकनीकी शिकायतों का मौके पर समाधान किया जाएगा।उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं।कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जनसुविध ा के संकल्प के साथ कार्य कर रही है तथा भविष्य में भी आम जनता के हित में इसी प्रकार के निर्णय लिए जाते रहेंगे।

विश्व थैलेसीमिया दिवस पर एनएचएम में रक्तदान शिविर, 71 यूनिट रक्त संग्रहित

लखनऊ, (संवाददाता)। विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए सुरक्षित एवं पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराना तथा आमजन में स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।रक्तदान शिविर का आयोजन राजकीय रक्त केंद्र, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वैच्छिक रक्तदान किया। शिविर के दौरान कुल 71 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया।स्टेट ब्लड सेल के प्रभारी एवं महाप्रबंधक डॉ. सूर्यांशु ओझा ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्त किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता और आवश्यकता के समय रक्त तभी उपलब्ध हो पाएगा।

बरात गए युवक की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस कर रही जांच घरवालों का रो–रोकर बुरा हाल

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी के रायबरेली में बरात गए युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। खबर मिली तो घर में चीख पुकार

मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। आगे की कार्रवाई की जा रही है। डीह थाना क्षेत्र के शेरनाथपुर गांव निवासी बृजेंद्र कुमार (22) शुक्रवार को क्षेत्र के ही पूरे कलंदर मजरे निनावां गांव बारात में गया था। बराती डीजे की धुन पर डांस कर रहे थे। इसी समय युवक की तबीयत खराब हो गई। साथियों ने उसे चारपाई पर लिटा दिया। रात लगभग 2 बजे युवक को लेकर उसके साथी बेहोशी की हालत में सलोन स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। मृतक की मां श्रीमती दहाड़े मार–मारकर रोने लगीं। मुंह से सिर्फ यही निकलता की अबहिन तो हमार भइया ठीक ठीक गयेन रहे, ई का होइ गवा। वहीं पिता जियाराम व बड़ा भाई मनोज सहम से गए। आंखों से सिर्फ अश्रुओं की धारा बह रही थी। सूचना पर एसओ जितेंद्र मोहन सरोज व चौकी इंचार्ज मोहित कुमार मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसओ जितेंद्र मोहन सरोज ने बताया की युवक की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। मामले की जांच की जा रही है।

नेक मानक के अनुरूप तैयार करें पीपीटी, कुलपति के सख्त निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक पालीवाल पार्क परिसर स्थित बृहस्पति भवन में आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश की ओर से प्रस्तावित समीक्षा बैठक को लेकर महाविद्यालयों की तैयारियों की समीक्षा करना रहा। कुलपति ने सभी महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्देशित किया कि वे अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता, उपलब्धियों, नवाचारों और संस्थागत गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें। बैठक में यह भी निर्देश दिए कि सेल्फ फाइनेंस और प्रबंध समिति के बजट को अलग–अलग दर्शाया जाए। कुलपति ने प्रधानमंत्री ऊषा योजना के अंतर्गत संभावित अनुदान को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालयों से 100 वर्षों की विकास योजना तैयार करने को कहा। इसमें नई इमारतों, अधोसंरचना विकास, स्मार्ट क्लास, प्रयोगशालाओं और शैक्षिक विस्तार की योजनाएं शामिल करने के निर्देश दिए गए। साथ ही महाविद्यालयों को अपनी कमियों और चुनौतियों को भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए कहा। बैठक में विद्यार्थियों की उपलब्धियों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों, शोध गतिविधियों, आउटरीच कार्यक्रमों और छात्र कल्याण योजनाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। कुलपति ने कहा कि महाविद्यालयों की गतिविधियां प्रस्तुति में स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। इसके लिए फोटो एवं आंकड़ों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाए। सभी फोटोग्राफ जियो टैग और कैप्शन सहित लगाने तथा प्रत्येक स्लाइड में अधिकतम दो फोटो रखने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में कुलसचिव अजय कुमार मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश उपस्थित रहे। कुलपति ने कहा कि सभी महाविद्यालय अपनी पीपीटी नेक मानकों के अनुरूप तैयार करें। यदि किसी महाविद्यालय का पूर्व में नेक मूल्यांकन हो चुका है ।

रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो चालकों का कब्जा, भीषण जाम में फंस रहे लोग

लखनऊ, (संवाददाता)। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के बाहर अव्यवस्थित यातायात और ऑटो चालकों की मनमानी यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। हालात यह हैं कि ट्रेन आने से पहले स्टेशन के दोनों ओर करीब एक किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। जाम में एंबुलेंस और अन्य इमरजेंसी वाहन तक घंटों फंसे रहते हैं। कई बार यात्री भी जाम में फंसने के कारण ट्रेन तक नहीं पकड़ पाते। स्टेशन पर आने वाली प्रमुख ट्रेनों में अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, आगरा फोर्ट इंटरसिटी, लखनऊ इंटरसिटी और कोटा पैसेंजर शामिल हैं। ये ट्रेनें दो से तीन घंटे के अंतराल पर स्टेशन पहुंचती हैं। ट्रेन आते ही यात्रियों को लेने पहुंचे ऑटो चालक स्टेशन परिसर और मुख्य सड़क तक फैल जाते हैं। आरोप है कि कई ऑटो चालक स्टेशन के अंदर तक घुसकर सवारियों से खींचतान करते हैं। कई बार बाहर से आए यात्रियों को झांसे में लेकर उनसे अधिक किराया वसूला जाता है। स्टेशन परिसर की व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी पर है, लेकिन यात्रियों का कहना है कि समस्या के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौन बने हैं। जन संपर्क अधिकारी संजय गौतम ने बताया कि आरपीएफ और जीआरपी ने कई बार अभियान चलाकर उन्हें हटवाया है। साथ ही आने वाले समय में वहां से प्रमुख गाड़ियों के संचालन को ईदगाह रेलवे स्टेशन की तरफ किया जा रहा है। अछनेरा निवासी तरुण ने बताया कि काम से बाहर जा रहा था। बिजली घर चौराहे से आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में करीब एक घंटा लग गया। बहुत मुश्किल से ट्रेन पकड़ी है। ऑटो चालकों ने पूरे रास्ते को जाम कर रखा है। साथ ही सड़क के दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। सेमरा निवासी बिजेंद्र सिंह का कहना है कि अपनी पत्नी को छोड़ने आया था। गाड़ी जाम में फंस गई। ऑटो चालकों के हाथ तक जोड़े लेकिन पूरा रास्ता जाम था।

जिन गांव की आबादी 150 वहां भी मिलेगी पक्की सड़क, दूरदराज के इलाके भी जुड़ सकेंगे

लखनऊ, (संवाददाता)। आगरा विकास भवन के सभागार में शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026–27 की कार्य योजना अनुमोदन की बैठक हुई। इसमें जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों को ई–विश्वकर्मा 2.0 पोर्टल पर दर्ज किया है। इसके साथ ही पिछले वर्ष के लंबित प्रस्तावों को शामिल किया है। वहीं, 150 से अधिक और एक किलोमीटर की दूरी वाले गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। इन प्रस्तावों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, धार्मिक मार्गों का चौड़ीकरण, अंतरराज्यीय सीमाओं पर सड़कों का सुदृढ़ीकरण और राज्य राजमार्गों के कार्य शामिल हैं। इसमें प्रमुख जिला मार्गों का चौड़ीकरण, केंद्रीय मार्ग और अवसंरचना निधि के कार्य और सेतु निर्माण भी सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 150 से अधिक आबादी और एक किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले मार्ग शामिल हैं। धार्मिक मार्गों के तहत पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं वाले पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों के प्रस्ताव हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमाओं पर पड़ने वाले मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य भी योजना का हिस्सा हैं। पिछले वर्ष के लंबित प्रस्तावों को भी इस कार्ययोजना में शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने की दिशा में तेजी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने ग्रेटर नोएडा स्थित यॉटा डेटा सेंटर पार्क का दौरा कर वहां विकसित अत्याधुनिक डिजिटल अवसंरचना और परिचालन व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर उनका स्वागत यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हिमांशु कौशिक द्वारा किया गया।दौरे के दौरान मंत्री को डेटा सेंटर पार्क की तकनीकी क्षमताओं, प्रमुख उपलब्धियों और उत्तर प्रदेश की डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यॉटा प्रबंधन ने बताया कि कंपनी प्रदेश में अपने निवेश और परिचालन का तेजी से विस्तार कर रही है तथा 125 मेगावाट स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य पर कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना प्रदेश के डिजिटल अवसंरचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।मंत्री ने बड़े पैमाने पर संचालित डेटा सेंटरों की विद्युत और जल आवश्यकताओं तथा उनसे जुड़ी चुनौतियों की भी जानकारी प्राप्त की। इस पर प्रबंधन ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में निरंतर सहयोग दिया जा रहा है, जिससे उद्योग और सरकार के बीच मजबूत समन्वय स्थापित हुआ है। दौरे के दौरान डेटा सेंटर में अपनाई गई वायु शीतलन तकनीक की भी जानकारी दी गई। प्रबंधन ने बताया कि इस तकनीक के माध्यम से शीतलन के लिए मीठे पानी की आवश्यकता को काफी हद तक कम किया गया है।

थानों के थानाध्यक्ष उठाना जरूरी नहीं समझते सीयूजी पर आने वाले कॉल

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। इस समय सीयूजी नंबर पर बात करना विभिन्न थानों पर तैनात थानाध्यक्ष जरुरी नहीं समझते है।जबकि पुलिस महानिदेशक का सख्त निर्देश है कि प्रदेश के सभी जिलों के एसएसपी,एसपी,व सीओ,थानाध्यक्ष के सीयूजी पर सभी फरियादियों को संतोष जनक उत्तर दें।मजे कि बात तो यह है जिले के एसएसपी, एसपी ग्रामीण,एसपी सिटी व विभिन्न सर्किल के सीओ का सीयूजी नबंर पर आने वाले फोन का जबाब तो फरियादियों के मुताबिक तो देते है लेकिन विभिन्न थानों के थानाध्यक्ष व प्रभारी निरीक्षक सीयूजी फोन पर काल जाने के बावजूद भी नहीं उठाते।जिसके चलते फोन करने वाले फरियादी अपनी समस्या के समाधान के लिए संबंधित थानों, सर्किल आफिस व मुख्यालय पर आना पडता है। जिससे कि उनका समय और धन दोनों बर्बाद होता है।यह गंभीर समस्या कोतवाली अयोध्या, थाना राम जन्मभूमि, रुदौली, कुमारगंज,थाना हैदरगंज, तारुन, पूरा कलंदर, खंडासा, पटरंगा, बाबा

बाजार सहित खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थानों पर है।इन जगहों पर तैनात थानाध्यक्षों के सरकारी नंबर पर फोन जाता नहीं है।अगर जाता भी है तो पूरी कॉल होने के बावजूद भी थानाध्यक्ष फोन उठाना मुनासिब तक नहीं समझते है।एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने खुद माना कि यह एक गंभीर समस्या है।क्योंकि कोई भी फरियादी सबसे पहले किसी भी समस्या को अपने थाने में तैनात थानाध्यक्ष से बताते हैं।अगर उनकी यह फरियाद संबंधित थानों के थानाध्यक्ष के सरकारी नंबर पर नहीं सुनी जाती है तो बहुत ही चिंता जनक की बात है। उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष सीयूजी नंबर पर आने वाले फोन का जबाव अवश्य दे।अगर उस समय वह किसी भी बैठक में है तो उसके बाद वे कालर को कल बैंक कर बात करे।उन्होंने कहा कि अगर सरकारी नंबर पर जवाब न देने वाले किसी भी थानाध्यक्ष की शिकायत उनके पास आती है तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

वर्ष 2027 मे विधानसभा सभा चुनाव मे पांच कायस्थ प्रत्याशियों की घोषणा कर रचा इतिहास

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। वर्ष 2027 मे होने वाले विधानसभा चुनावों में कायस्थ समाज ने लखनऊ में पांच प्रत्याशियों की घोषणा कर इतिहास रचा।सोमवार को कायस्थ समाज द्वारा होटल जयति ओएसिस इन इन्दिरा नगर में व वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कायस्थ समाज की भूमिका व कायस्थ मांगे अपना अधिकार विषय पर महात्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन हुआ।मुख्य संयोजक व प्रदेश अध्यक्ष शेखर कुमार ने 2027 में होने वाले सभी को सकारात्मक चर्चा में भाग लेने का विनम्र आग्रह किया। सभी ने प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करते हुए सभी विधानसभा के सशक्त उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पर लखनऊ की सभी विधानसभा से आए हुए प्रमुख जन व लखनऊ की समस्त कायस्थ समितियोंध्संगठनों के प्रतिनिधियों के विचार आए और सभी ने एकमत से प्रदेश अध्यक्ष शेखर कुमार को अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार देते हुए कायस्थ पाठशाला के लखनऊ के मेम्बर इंचार्ज व कायस्थ समाज के विभिन्न संगठनों कार्य करने का अनुभव रखने वाले आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव को मध्य विधानसभा,चित्रांश एवं लोक सेवा समाज, केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कृष्ण श्रीवास्तव को उत्तरी विधानसभा,पूर्व में कैन्ट विधानसभा से चुनाव लड़ चुके व ब्राइट वे कान्वेंट कालेज के प्रबन्धक अविनाश श्रीवास्तव को कैन्ट विधानसभा से वरिष्ठ व्यापारी नेता व कायस्थ समाज के विभिन्न संगठनों में कर्मठता से अपनी

पहचान बनाने वाले सुशील कुमार श्रीवास्तव को पश्चिमी विधानसभा,ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष व संगत पंगत के सह प्रमुख ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव को सरोजनी नगर का करतल हर्षोल्लासध्वनियों के साथ शेखर कुमार ने सबकी सहमति पर अपनी मुहर लगाते हुए घोषणा की।परिचर्चा में आए हुए महर्षि विद्या मंदिर के प्रबंधक व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनूप कुमार श्रीवास्तव ने सभी प्रत्याशियों को माला व पटका पहनाकर बधाई दी।उसके बाद काफी संख्या में उपस्थिति लोगों ने भी सभी प्रत्याशियों को माला पहनाकर बधाई दी।कार्यक्रम में अपनी विशेष सहभागिता व उपस्थिति लखनऊ खण्ड स्नातक विधान परिषद प्रत्याशी आर्कीटेक्ट सुनील कुमार श्रीवास्तव जी ने भी माला पहनाते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आलोक भटनागर, राजेश श्रीवास्तव,शैलेन्द्र कुमार,संजय श्रीवास्तव,नीरज श्रीवास्तव,दिनेश खरे,मनोज सक्सेना,सचिन,आलोक श्रीवास्तव,अतुल श्रीवास्तव, सचिन लाल,आनन्द कुमार,शरद,नरेश प्रधान,विमलेश,विनोद श्रीवास्तव,मनोज कुमार, मयंक श्रीवास्तव,सुनीता श्रीवास्तव, श्रद्धा श्रीवास्तव,प्रीति श्रीवास्तव,निधि श्रीवास्तव, डाक्टर नविता श्रीवास्तव,अम्रिता करें सहित काफी संख्या में सभ्रांत लोगों उपस्थिति की रही।अन्त में मुख्य संयोजक व प्रदेश अध्यक्ष ने सभी घोषित प्रत्याशियों को माला पहनाकर सम्मानित करते हुए बधाई दिया।इस मौके सभी प्रत्याशियों से आग्रह किया कि 11 जून तक अपने क्षेत्रों से 51सम्मानित लोगों की सूची के साथ साथ कैम्प कार्यालयों का चयन करते हुए क्षेत्रों की समस्यायों को प्रथामिकता से निराकरण करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहते हुए अपनी अलग पहचान बनायेंगे।

कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मिलकर विभिन्न समस्याओ से कराया अवगत

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह के अगुवाई में डीएम शशांक त्रिपाठी से मिलकर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया।जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने बताया कि इन समस्याओं में प्रमुख रूप से पूरा ब्लॉक के गंगौली में गेहूं खरीद केंद्र पर विगत 15 दिन से गेहूं खरीद न होने से किसान परेशान है।इसी के साथ जनपद में कई गेहूं खरीद केंद्रों पर खरीद सही ढंग से नहीं हो पा रहा है जिसे तुरंत संज्ञान में लेकर कृत कार्यवाही का अनुरोध किया। श्री पाठक ने बताया कि कांग्रेस प्रतिनिध मंडल ने नगर में जीर्ण शीर्ण पढ़े प्रख्यात विद्वान विचारक आचार्य नरेंद्र देव के नाम से नरेन्द्रालय प्रेक्षागृह जो कई वर्ष से बदहाल स्थिति में पड़ा है।यह प्रेक्षागृह आम लोगों के लिए कम पैसे में सार्वजनिक ,राजनीतिक, शादी विवाह पर उपलब्ध रहता था जिसे नगर पालिका के लिए कूड़ा घर बना दिया गया है।कांग्रेस प्रतिनिध मंडल ने नगर वासियों के लिए नरेन्द्रालय प्रेक्षागृह अति आवश्यक बताया।श्री पाठक ने बताया शहर के चौराहों पर जाम कम करने के लिए डिवाइडर बनाया जाने का अनुरोध किया है।इस मौके पर पीसीसी सदस्य पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा, पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा ,उपाध्यक्ष उमेश उपाध्याय, महामंत्री अनिल तिवारी ,ब्लॉक अध्यक्ष सोहावल राजेंद्र प्रसाद, धर्मेंद्र सिंह फास्टर, राम सागर रावत आदि प्रमुख लोग रहे।

300 शैय्यायुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण कार्य का डीएम ने किया निरीक्षण

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।जनपद अयोध्या में ईपीसी मोड पर जी.7 मॉडल के तहत निर्माणाधीन 300 शैय्यायुक्त चिकित्सालय भवन का जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने स्थलीय निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि कार्य निर्धारित

मानकों के अनुरूप एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता निर्माण खंड–2 को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में आ रही सभी बाधाओं को समय रहते दूर करते हुए कार्यों में तेजी लाई जाए,ताकि परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण हो सके।उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह चिकित्सालय जनपदवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड–2 सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं निर्माण कार्य से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सीएमआईएस पोर्टल पर फीड परियोजनाओं एवं सीएम डैशबोर्ड की जिलाधिकारी ने की समीक्षा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।डीएम शशांक त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सीएमआईएस पोर्टल पर फीड विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा बैठक की। बैठक में माह अप्रैल 2026 के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई।समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पीपीपी मॉडल की परियोजनाओं, यूपी कॉरपोरेशन, जिला कारागार में निर्माणाधीन कार्यों, पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं, गोरखपुर–अयोध्या मार्ग निर्माण, रामपथ, धर्मपथ, राजघाट, राम की पैड़ी, रुदौली स्थित मां कामाख्या मंदिर निर्माण, बृहद गो संरक्षण केंद्र, कोटिया, सेतु निगम के विभिन्न कार्यों, गोसाईगंज में तमसा नदी पर सेतु निर्माण, बेसिक शिक्षा विभाग के कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण कार्य तथा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग से संबंधित कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने अधिशासी अभियंता निर्माण खंड–2 को निर्देशित किया कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए।सीएम डैशबोर्ड के विकास एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने फैमिली आईडी की प्रगति बढ़ाने, पर्यटन विभाग की धीमी परियोजनाओं में गति लाने तथा पोषण अभियान में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिला कार्यक्रम अधिकारी से पोषण अभियान

में धीमी प्रगति पर कारण पूछा गया तथा चेतावनी दी गई कि प्रगति में सुधार न होने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड से नई सड़कों के निर्माण में देरी पर जवाब तलब करते हुए शीघ्र प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया। किसान सम्मान निधि एवं पीएम कुसुम योजना में बेहतर प्रगति लाने पर विशेष जोर दिया गया।मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को पोल्ट्री क्षेत्र तथा मत्स्य विभाग को अपनी रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।वहीं जिला प्रोबेशन अधिकारी को वृद्धावस्था पेंशन योजना में शत–प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग एवं मंडी परिषद के कार्यों की सराहना की तथा आगे भी इसी प्रकार की प्रगति बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संपत्ति नामांकन को 'ए' ग्रेड में लाने, खनन विभाग की रैंकिंग 'बी' ग्रेड से 'ए' ग्रेड में सुधारने तथा स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन कार्यों में सुधार के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश पोर्टल पर सभी कार्यों की फीडिंग सही एवं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने को कहा, ताकि जनपद की रैंकिंग बेहतर प्रदर्शित हो।जिलाधिकारी ने आईजीआरएस की अलग से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन विभागों द्वारा शिकायतों का संतोषजनक निस्तारण नहीं किया जाएगा, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने खंड विकास अधिकारी अमानीगंज, खंड विकास अधिकारी सोहावल, अधिशासी अभियंता नगर पालिकाध्नगर पंचायत, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बंदोबस्त अधिकारी, जिला कमांडेंट होमगार्ड, एआर कोऑपरेटिव, खंड शिक्षा अधिकारी मिल्कीपुर, एबीएसए तारुन, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बीकापुर, जिला पूर्ति निरीक्षक बीकापुर, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी रुदौली को निर्देश दिए कि शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करते हुए आख्या समय से पोर्टल पर अपलोड की जाए।बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को जनता दर्शन को गंभीरता से लेने तथा शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (एफआर) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

रामायण कालीन वृक्षों से रामनगरी को आच्छादित करेगा नगर निगम – मेयर

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। जगह–जगह उपवन स्थापित कर अयोध्या को रामायणकालीन वृक्षों से आच्छादित किया जाएगा।इसके अलावा मुख्यमंत्री नगरोदय योजना के तहत डिजिटल लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। इस संबंध में महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी एवं नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने निर्देश दिए हैं।वह नगर निगम के अधिकारियों के साथ नगर में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।महापौर ने कहा कि नगर क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर से छोटा एवं बड़ा दोनों श्रेणी के उपलब्ध स्थानों का चयन कर लिया जाये और वहां रामायण कालीन वृक्षों को रोपा जाए। इसके लिए जैन मंदिरों के आसपास जमीन तलाशने का भी निर्देश उन्होंने दिया।नगर आयुक्त ने हीट एक्शन प्लान के मुताबिक अति संवेदनशील नौ वार्डों में इस योजना के तहत विशेष फोकस करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में बताया गया कि नगर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति के दो उपवन स्थापित किए गए हैं।बैठक में मुख्यमंत्री नगरोदय योजना के तहत डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए छात्रों के बहुलता वाले इलाकों वशिष्ट कुंड, चित्रगुप्त, मलिकपुर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि वार्डों में जगह तलाश करने का भी निर्देश दिया गया। तय किया गया कि नगर निगम निधि से नगर के पांच छोटे

तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराकर उनकी वेरीकेटिंग कराई जाएगी और वहां जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। नगर आयुक्त ने समीक्षा के दौरान कहा कि जिन निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है, उनके भुगतान को भी समय से सुनिश्चित करा दिया जाय। उन्होंने कार्य में जानबूझकर छह माह से अधिक विलंब करने वाले ठेकेदारों को चिन्हित कर नोटिस दिए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना के तहत निर्मित चार स्कूलों का लोकार्पण स्कूल खुलते ही कराने को कहा।

भजन संध्या स्थल के पास पार्किंग एवं शौचालय के निर्माण की योजना को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया। समीक्षा बैठक में पाया गया कि स्वीकृत पांच तालाबों का निर्माण कार्य चल रहा है, इस परियोजना को समय से पूरा कराने की हिदायत दी गई।बैठक में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि 32 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि बाकी 30 परियोजनाओं को जल्द पूरा कराने को कहा गया। सीएम ग्रिड योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 के 25 कार्य पूर्ण पाए गए। बताया गया कि सीवरेज एवं जल निकासी के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत दो कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, जबकि दो कार्य सीवर लाइन के कारण बाधित हैं। समीक्षा बैठक में अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, मुख्य अभियंता सिविल पुनीत कुमार ओझा के अलावा संबंधित विभागों के अभियंता एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

जिले के 18 थानों के शास्त्रागारों में जंग खा रहे 800 से अधिक असलहे

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। जिले के 18 थानों के शास्त्रागारों में 800 से अधिक असलहें शस्त्रागार के एक कोने मे जंग खा रहे हैं।इन असलहों को संबंधित थाना क्षेत्रों के पुलिस ने चुनाव, किसी विवाद,हर्ष फायरिंग सहित अन्य मामलों में इन थानों के शास्त्रागारों में जमा कराया था।आज तक इन असलहों के स्वामियों द्वारा थानों पर जमा असलहा न ले जाने के चलते जंग खा रहे हैं।बताते चलें कि जिले के 18 थानों में कुल 1102 असलहे विभिन्न मामलों में पुलिस द्वारा जमा कराए गए थे जिनमें से महज 216 असलहे ही संबंधित स्वामी ले गए जबकि शेष 886 असलहे इन थानों के शस्त्रागार के एक कोनें मे कबाड़ के रुप मे शोभा बढा रहे हैं।एसएसपी कार्यालय के मुताबिक अभी तक कोतवाली नगर में 28,थाना कैंट में 45, कोतवाली अयोध्या में 46, राम जन्मभूमि थाना में 11, पूरा कलंदर थाना में 47 असलहे शस्त्रागार में पड़े हैं।जबकि इसी तरह थाना गोसाईगंज में 26, थाना महाराजगंज में 57, थाना रौनाही में 82, असलहे शस्त्रागार में कबाड़ के रूप में है।वही कोतवाली बीकापुर में 47, हैदरगंज में 40, तारुन में 25, इनायत नगर में 106, कुमारगंज में, 2 खंडासा में 69, रुदौली में 77,मवई में 86,बाबा बाजार में 8, तथा पटरंगा थाना में 79 असलहे कबाड़ के रूप में शस्त्रागार की शोभा बढ़ा रहे हैं।देखा जाए तो इन असलहों को पुलिस ने चुनाव के समय,लड़ाई झगड़ा या फिर हर्ष फायरिंग या किसी अन्य मामले में संबंधित थानों के पुलिस कर्मियों द्वारा थानों पर जमा कराया गया था।परंतु अभी तक उनके स्वामी इसे नहीं ले गए।इस संबंध में एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि इन असलहों को ले जाने की सूचना बीच–बीच में संबंधित थानों के पुलिस द्वारा इसके स्वामियों को नोटिस के रूप में दी जाती है परंतु इसके बावजूद थानों पर जमा असलहों के स्वामी इसे ले जाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं।

महिला एसओ आशा शुक्ला ने महिला उप निरीक्षक श्वेता राठौर के साथ महिलाओ को किया जागरुक

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। सोमवार को एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर तथा मिशन शक्ति फेज 5 के नोडल प्रभारी व एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी के निर्देश पर सीओ सिटी श्रीयेश त्रिपाठी की देखरेख मे महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने महिला उप निरीक्षक श्वेता राठौर ने महिला कांस्टेबल शशिलता व शालिनी के साथ जिला महिला चिकित्सालय,जिला पुरुष चिकित्सालय, रिकाबगंज, बल्लाहाता, चौक रोडवेज, गुरुगोविंद सिंह चौक, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन सहित अन्य प्रमुख चौराहा तथा मार्गों पर महिलाओ व बेटियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक किया।इस मौके पर उन्होंने मिशन शक्ति अभियान फेज फाइव के तहत सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी देते हुए बताया कि जिससे कभी भी संकट के समय आप अपनी सुरक्षा कर सकती हैं।इस मौके पर उनके साथ मौजूद रही महिला उप निरीक्षक श्वेता राठौर ने

बालिकाओं से कहीं।उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए जहां एक तरफ उनके विकास को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण सुकन्या समृद्धि योजना सहित एक से बढ़कर एक कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चल रही हैं।इस मौके पर उन्होंने वहां पर मौजूद बालिकाओं को पंपलेट व बैनर पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना का अंदेशा हो तो बिना झिझक अपने नजदीकी पुलिस कर्मियों, महिला थाना तथा अपने परिजनों को फोन पर बताये।इस मौके पर उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।

अभी अयोध्या डिपो बस स्टैंड को लखनऊ जैसे हाईटेक पीपीपी मॉडल बनने में लगेगा समय

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।अभी शहर के सिविल लाइन स्थित अयोध्या डिपो बस स्टैंड को लखनऊ जैसे हाईटेक पीपीपी मॉडल बस स्टैंड का रूप लेने में समय लगेगा।हां इतना जरूर है कि इस बस स्टैंड को लखनऊ जैसे हाईटेक पीपीपी मॉडल बनाने की कवायद पिछले वर्ष महीनो से शुरू हो गई है। क्योंकि शासन से इस बस स्टैंड को हाईटेक पीपीपी मॉडल बस स्टैंड में बनाने की सूची में रखा गया है।जिससे कि इधर से गुजरने वाले बस यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके लिए शासन से जैसे ही टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी,उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।सबकुछ ठीक ठाक रहा तो सिविल लाइन अयोध्या डिपो बस स्टेशन चमाचम दिखेगी।यह रोडवेज स्टेशन लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तरह पीपीपी मडल पर चमाचम दिखेगा।जहाँ पर एक ही छत के नीचे बस यात्रियों को सभी रूटों

पर जाने के लिए एक से बढ़कर एक लग्जरी बसे उपलब्ध रहेगी।वहीं रोडवेज स्टेशन के परिसर में हाइटेक माल, काम्प्लेक्स, दुकानें उपलब्ध रहेगी।इस मामले पर सहायक प्रबंधक रोडवेज आदित्य प्रकाश ने बताया कि अयोध्या बस स्टेशन को हाइटेक पीपीपी माडल बनाने के लिए पिछले वर्ष सितंबर माह में ही चयन कर लिया गया था।जिसकी प्रक्रिया लगभग लगभग पूरी हो चुकी है शीघ्र ही इसके निर्माण कार्य के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शासन से जारी होगी।बताया कि आलमबाग रोडवेज बस स्टैंड की तरह ही अयोध्या बस स्टेशन पर भी सभी सुविधाएं बस यात्रियों को मिलेगी।यहां से भिन्न–भिन्न रूटों पर महानगरों को जोड़ने के लिए एक से बढ़कर एक लग्जरी बसों का संचालन किया जाएगा।जिससे कि अयोध्या जिले में आने वाले यात्रियों को आने जाने में किसी तरह की कोई कठिनाइयां ना उत्पन्न हो।बताया कि इसके साथ ही साथ यहां पर हाइटेक कार्यशाला के रूप में भी निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि शासन की प्रथम प्राथमिकता अयोध्या में राम मंदिर होने के चलते अब श्रद्धालुओं की आवाजाही लाखों की संख्या में हो रही है।जिसमें सिर्फ देश के ही विभिन्न प्रांतो से ही नहीं बल्कि देश–विदेश के भी पर्यटक वास श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं।इस सभी को देखते हुए जैसे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, महार्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या का निर्माण किया गया है।ठीक उसी तरह से अयोध्या बस स्टैंड को भी पीपीपी मडल में हाइटेक करने के लिए शासन द्वारा चयनित किया गया है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।